



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 1992/चैत्र 6, 1914

No. 133]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1992/CHAITRA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1992

सा. का. नि. 365(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन
न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132
की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पत्तन
न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ
संलग्न अनुसूची में मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी [अवकाश यात्रा
सुविधा (संशोधन)] विनियम, 1992 का अनुमोदन करती
है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र
में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12016/29/91-पी.ई. I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा सुविधा)
संशोधन विनियम, 1992

793 GI/92

अनुसूची

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
की धारा-28 के खंड (बी) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों
के अनुपालन में तथा इस विषय पर वर्तमान विनियमों का
अधिक्रमण करते हुए मुंबई पोर्ट का विश्वस्त मंडल कथित
अधिनियम की धारा-124 की उपधारा (1) की आवश्यकता-
नुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेकर निम्नलिखित
विनियम बनाता है। ये विनियम उक्त धारा-124 की उप-
धारा (2) की आवश्यकतानुसार राजपत्र के पिछले दो
लगातार अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं। ये विनियम हैं:

वर्तमान विनियम क्र. 1 से 27 के बड़े निम्न शामिल
करें—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:

(1) ये विनियम “मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश
यात्रा सुविधा) संशोधन विनियम—1992”
कहा जाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित
होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिचाया : इन विनियमों में अन्यथा प्रयोजन
आवश्यक न हो तब तक,

- (1) मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विभाग प्रमुख के अर्थ वे ही रहेंगे, जो उन्हें मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में क्रमशः प्रदान किए गए हैं।
- (2) लेखा अधिकारी से तात्पर्य है—मंडल का वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और इन विनियमों के अंतर्गत कर्मचारियों के दावों का नियमन करने के लिए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा नामित मंडल के लेखा विभाग का/के कोई अन्य अधिकारी।
- (3) सुविधा से तात्पर्य है इन विनियमों के अंतर्गत देय अवकाश यात्रा सुविधा।
- (4) कर्मचारी से तात्पर्य है मंडल का कर्मचारी।
- (5) भारत में स्थित स्थान से तात्पर्य है कोई भी स्थान जो भारत के क्षेत्र/सीमाओं में आता फिर चाहे वह महाद्वीप में हो या समुद्रीपार।
- (6) लघुतम सीधे मार्ग से तात्पर्य वही है जो पूरक नियम-30 में और उसके अंतर्गत समय-समय पर जारी आदेशों में अभिप्रेत है।
- (7) दो वित्तीय वर्षों की अवधि में एक बार से तात्पर्य है—वित्तीय वर्ष 1975-76 में आरंभ होने वाले दो वित्त वर्षों के प्रत्येक खंड (ब्लॉक) में एक बार।
- (8) चार वित्तीय वर्षों की अवधि में एक बार से तात्पर्य है—वित्तीय वर्ष 1975-76 से आरंभ होने वाले चार वित्त वर्षों के प्रत्येक खंड (ब्लॉक) में एक बार।

2. (1) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर बाकी स्थितियों में यह सुविधा मंडल के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मिल सकती है, इनमें निम्न भी शामिल हैं :—

- (ए) "बी" श्रेणी के किनारा मजदूर, और
- (बी) ठेके पर रखे गए कर्मचारी;

यदि ठेके की अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो ठेके पर रखा गया प्रत्येक कर्मचारी अविरत सेवा का एक वर्ष पूर्ण होने पर उक्त सुविधा प्राप्त करने के योग्य होगा।

यदि प्रारंभिक ठेका एक वर्ष का है, लेकिन बाद में उसकी अवधि बढ़ायी जाती है, तो उपरोक्त सुविधा देने के लिए ठेके की पूर्ण अवधि गिनती में ली जाएगी।

ठेके पर लिए गए कर्मचारियों को उक्त सुविधा निम्न शर्तों पर दी जाएगी—

- (i) ऐसे कर्मचारियों के मामले में दो वर्ष के क्रमिक खंड या चार वर्ष के क्रमिक खंड की गणना उनके मंडल की सेवा में पद स्वीकार करने की प्रत्येक तिथि से की जाएगी।
- (ii) जब संबंधित कर्मचारी उपरोक्त सुविधा लेना चाहेगा तब उचित प्रशासनिक प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा, कि वह कर्मचारी दो वर्ष या चार वर्ष—जैसा भी मामला हो—तक मंडल की सेवा में रहने की पर्याप्त संभावना है, बाद के तुरंत दो वर्षों या चार वर्षों—जैसा भी मामला हो—खंड के दौरान भी यह सुविधा इन्हीं शर्तों पर प्राप्त होगी।

(सी) पुनः सेवा में लगे निवृत्त कर्मचारी :

जो कर्मचारी निवृत्त होकर पुनः काम पर लगे हो, उन्हें अखंड सेवा का एक वर्ष पूर्ण होने पर उपरोक्त विनियम (बी) में उल्लिखित शर्तों पर अवकाश यात्रा सुविधा मिल जाएगी, लेकिन निवृत्ति के तुरंत बाद ही पुनः सेवा में लगे हो, तो यह सुविधा और पुनः सेवा की अवधि के लिए समतुल्य सुविधा-प्रदान करने के लिए पुनः सेवा की अवधि पिछली सेवा से जुड़कर ही गिनी जाएगी (बशर्ते कि यदि कर्मचारी निवृत्त ना होता, तो उसे यह सुविधा देय होती)।

(डी) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर आए हुए राज्य सरकार/केंद्र सरकार/स्वायत्त संस्था/एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी उपरोक्त सुविधा प्राप्त होगी।

(2) उक्त सुविधा निम्न को प्राप्त नहीं होगी :

(ए) जो नौकरी की शर्तों के अनुसार निशुल्क पास अथवा प्रिविलेज टिकट आर्डर्स पाने के लिए पात्र हैं, ऐसे रेलवे विभाग के तथा यांत्रिकी अभियंता विभाग के तथा लोको एवं बेगन स्थापना विभाग के कर्मचारी।

(बी) जिन्हें पहले दिए जाने वाले निशुल्क पास अथवा प्रिविलेज टिकट आर्डर्स के बदले अब विशेष यात्रा भत्ता महाधार दिया जाता है, ऐसे रेलवे विभाग के और सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रेलवे इंजीनियरिंग शाखा के कर्मचारी।

(सी) मंडल की पूर्णकालिक नौकरी में नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति, और

(डी) जिनका भुगतान आकस्मिक खर्च में से किया जाता है, वे व्यक्ति

(3) कर्मचारी अथवा उसका परिवार : जैसा भी मामला हो—जिस तिथि पर अपनी यात्रा आरंभ करता है, उस तिथि को यदि कर्मचारी को अविरत सेवा का एक वर्ष पूरा नहीं हुआ होगा, तो उस कर्मचारी को उक्त सुविधा देय नहीं होगी, सुविधा

देय होने के लिए यात्रा की शुरुवात की तिथि पर अविरत सेवा का एक वर्ष पूर्ण होने की शर्त स्थायी व परिवीक्षाधीन कर्मचारियों तथा अस्थायी स्थानापन्न कर्मचारियों—सभी पर बराबर लागू होगी।

टिप्पणी:—

(ए) मंडल का जो कर्मचारी निलंबित किया गया हो, वह अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि निलंबन अवधि के दौरान वह आकस्मिक छुट्टी सहित किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं ले सकता। परन्तु चूंकि निलंबन अवधि में भी वह सेवा में बना रहता है, उसके परिवार के सदस्य उक्त सुविधा लाभ ले सकते।

(बी) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्रति नियुक्ति पर आए अधिकारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा—जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पोर्ट ट्रस्ट में आए हैं, उन्हें भी अवकाश यात्रा सुविधा अपने आप देय होगी। इस विषय में सुस्पष्ट संजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(सी) यदि केन्द्रीय लोक सेवा के अवकाश यात्रा सुविधा नियमों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार के परिवर्तन पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए भी उसी तिथि से, मंडल की अनुमति से लागू होंगे।

4. हकदारी की बारंबारता :

(1) कर्मचारी को उक्त यात्रा सुविधा मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए दो वित्तीय वर्षों में एक बार तथा भारत में किसी भी स्थल की यात्रा के लिए चार वित्तीय वर्षों में एक बार दी जाएगी। इसके अंतर्गत कर्मचारी और उसके परिवार शामिल हैं।

(2) जिस कर्मचारी का परिवार उसके नौकरी के स्थान से दूर रहता है, वह कर्मचारी दो वित्तीय वर्षों के खंड में एक बार अपने लिए, और अपने परिवार—दोनों के लिए यात्रा सुविधा लेने के बजाय मूल निवास स्थान की यात्रा की सुविधा अपने अकेले के लिए हर खंड के प्रत्येक वर्ष में ले सकता है।

स्पष्टीकरण:—“दो वित्तीय वर्षों में एक बार” से तात्पर्य है—

वित्तीय वर्ष 1975-76 से आरंभ करते हुए दो वित्तीय वर्षों के बने एक खंड (ब्लॉक) में एक बार।

“चार वित्तीय वर्षों में एक बार” अर्थात् वित्तीय वर्ष 1975-76 से आरंभ करते हुए चार वर्षों के बने एक खंड में एक बार।

(3) जो कर्मचारी और उसका परिवार उक्त सुविधा का लाभ दो वर्षों के खंड में एक बार या चार वर्षों के खंड में एक बार प्राप्त नहीं कर पाया हो, उसे

वह सुविधा अगले दो वर्षों या चार वर्षों—जैसा भी मामला हो—खंड का प्रथम वर्ष समाप्त होने से पूर्व प्राप्त करने की अनुमति दी जाय।

(4) यदि वापसी यात्रा अगले वित्तीय वर्ष में की जाती है, तो यह माना जाएगा कि उपरोक्त सुविधा जिस वित्तीय वर्ष में यात्रा आरंभ की गयी थी, उसी खंड में ली गयी।

5. हकदारी :

(1) सभी कर्मचारी दो वर्षों के खंड में एक बार अपने मूल निवास स्थान (होम टाऊन) तथा चार वर्षों के एक खंड में भारत के किसी भी स्थान के यात्रा की सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(2) उपरोक्त यात्रा का संपूर्ण प्रत्यक्ष खर्च मंडल वहन करेगा। कर्मचारी उच्च या निम्न वर्ग में यात्रा करे, तो उसमें मंडल को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल कर्मचारी को देय वर्ग के किराये की राशि, अथवा वास्तव में निम्न वर्ग से यात्रा की हो, तो उस निम्न वर्ग के किराये की राशि का भुगतान करेगा।

(3) जो कर्मचारी अपने मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह चार वर्षों के खंड में भारत के किसी भी स्थल की यात्रा के लिए यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र है, तथापि चार वर्षों के खंड में एक बार भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की सुविधा का लाभ ले लिया हो, तो यह माना जाएगा कि वह सुविधा ऐसी यात्रा (भारत के किसी भी स्थान की) जिस अवधि में की गयी, उस अवधि के लिए कर्मचारी को देय जन्मस्थल/मूल निवास स्थान की यात्रा की सुविधा (इसमें विनियम 4 के उप-विनियम “3” के अंतर्गत आगे लायी गयी सुविधा यदि हो—भी शामिल है) बदलने में ली गयी है—और तदनुसार समायोजन किया जाएगा। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर कर्मचारी मूल निवास स्थान की यात्रा की सुविधा आगे ले जाने (फॉरवर्ड करने) का हकदार है, तो ही उसे उसी वर्ष की भारत के किसी स्थान की यात्रा की भी सुविधा अगले खंड के प्रथम वर्ष तक आगे ले जाने का हक रहेगा।

(4) प्रत्येक मामले में यात्रा मूल निवास स्थान और वहां से वापसी की होनी चाहिए। और दावा—स्थान को जाने की रीति यात्राओं के लिए किया जाना चाहिए। कर्मचारी के खर्च के या उसके

परिवार के मामले में मूल निवास स्थान की यात्रा का आरंभ या अंत मुंबई से ही हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आर्थिक सहायता के रूप में यात्रा के प्रत्यक्ष अंतर से किराये की राशि ही देय होगी। यह राशि यात्रा मुंबई से कर्मचारी के मूल निवास स्थान के बीच की जाती, तो जितनी राशि देय होती, उतनी राशि तक सीमित होगी। ऊपरी किराया राशि—यदि हो—तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी मंडल की नहीं होगी।

6. परिवार की परिभाषा :

(ए) डाकतार विभाग के कर्मचारी को स्थानांतरण के समय यात्रा भत्ता देने के हेतु लागू किए जाने वाले 'मूल नियम' और पूरक नियम के डाकतार संकलन के समय-समय पर यथासंशोधित पूरक नियम 2(8) में दी गई "परिवार" की परिभाषा यहां अपनाई जायेगी। यदि पति-पत्नी दोनों (मंडल के) कर्मचारी हैं, उस मामले में परिवार को देय यात्रा सुविधा पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को देय श्रेणी के अनुसार होगी, दोनों को देय के अनुसार नहीं।

(बी) कर्मचारी और परिवार के स्वतंत्र यूनिट—

परिवार के सदस्य मंडल के कर्मचारी के साथ ही यात्रा करें, या जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी यात्रा करता है, उसी वर्ष में यात्रा करें, यह आवश्यक नहीं है, परिवार के सदस्य स्वतंत्र रूप से इस यात्रा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चाहे मंडल का कर्मचारी उस समय उस सुविधा का लाभ ले या न ले। परिवार के सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार एक साथ या अलग-अलग गुटों में अपनी यात्रा कर सकते हैं। यदि वे अलग-अलग समय पर भिन्न गुटों में यात्रा करते हैं, तो प्रत्येक गुट को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाय, बशत कि प्रथम गुट ने जिस खंड में यात्रा की है, उसी खंड की अवधि में यह यात्रा की जाय। प्रत्येक गुट की वापसी यात्रा उस गुट की यात्रा आरंभ होने की तिथि से छः महीने के अंदर पूर्ण होनी चाहिए। विशेष मामलों में विभाग प्रमुख तथा विभाग प्रमुखों के मामले में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष यह शर्त शिथिल कर सकते हैं।

(सी) मंडल का कर्मचारी और/अथवा परिवार सदस्य एक ही खंड में कोई मूल निवास स्थान की ओर या कोई भारत के किसी भी स्थल की यात्रा कर सकते हैं :

एक ही खंड में परिवार के कुछ सदस्य मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए और अन्य "भारत के किसी भी स्थल" की यात्रा के लिए उक्त सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

(डी) मंडल के कर्मचारी और/अथवा परिवार के सदस्य एक ही स्थान या भिन्न स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। "भारत के किसी भी स्थल" की यात्रा की सुविधा लेते समय मंडल का कर्मचारी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य एक ही स्थान या अपनी पसंद के अन्य स्थानों की यात्रा कर सकते हैं।

(इ) एक ही विधा यात्रा के लिए यात्रा सुविधा :

मंडल के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को यात्रा सुविधा आने और जाने की यात्रा के समय स्वतंत्र रूप से प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगी।

स्पष्टीकरण :

(i) सिर्फ प्रस्थान यात्रा की प्रतिपूर्ति का हकदार :
(1) निर्भर बेटा/बेटी—यदि वे मूल निवास स्थान जाने के बाद नौकरी में लगे/शादी करें/अगले अध्ययन के लिए वहीं रहने का निर्णय लें।

(ii) कर्मचारी का परिवार—यदि मूल निवास स्थान तक की यात्रा करने के बाद वहां से वापसी यात्रा करने का इरादा न हो, बशर्ते इसके लिए मंडल का कर्मचारी लिखित रूप से सहमति देगा कि यदि बाद में वापसी यात्रा की जाती है, तो वह उस यात्रा से संबंधित सुविधा का हद छोड़ने के लिए तैयार है।

(बी) सिर्फ वापसी यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार :

(i) मूल निवास स्थान से कर्मचारी के नौकरी के गांव आने वाला/आनेवाली नवविवाहित पति/पत्नी अथवा कर्मचारी का पति/पत्नी जो लंबे समय से मूल निवास स्थान में रहा/रही हो और जिसने प्रस्थान की यात्रा संबंधित यात्रा सुविधा का लाभ न उठाया हो,

(ii) कर्मचारी पर निर्भर पुत्र या पुत्री—जो अध्ययन के लिए/बाधा-दादी के साथ वास्तव्य के लिए मूल निवास स्थान पर रहे हो और अब अकेले/अपने माता-पिता के साथ लौट रहे हो।

(iii) कर्मचारी का बच्चा—जो पहले तीन साल से छोटा था, परंतु जिसके वापसी यात्रा के समय तीन वर्ष पूरे हुए हो।

(iv) मूल निवास स्थान में वास्तव्य के समय मंडल के कर्मचारी द्वारा कानूनन गोद लिया गया बच्चा।

नोट :

यदि कोई बच्चा प्रस्थान यात्रा के समय 12 वर्ष से कम उम्र का था, लेकिन जिसके वापसी यात्रा के समय 12 वर्ष पूरे हुए हो, तो प्रस्थान यात्रा के लिए आधा किराया तथा वापसी यात्रा के लिए पूरा किराया प्राप्त करने का हकदार होगा।

(एफ) यदि मंडल के कर्मचारी की पत्नी/का पति मंडल के अलावा अन्यत्र रोवारत हो, और वहां भी अवकाश यात्रा सुविधाएं उपलब्ध हो, तो मंडल के कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा के लिए दावा देने समय निम्न प्रकार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

“प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए मैंने अवकाश यात्रा सुविधा का दावा किया है, वह (सार्वजनिक उपक्रम/निगम स्वायत्त संस्था का नाम) में काम करता/करती है और वहां अवकाश यात्रा का लाभ मिलता है, लेकिन उसने इस सुविधा यात्रा के संबंध में उनके नियोक्ता के पास कोई दावा नहीं किया है और न करेगी/करेंगे।”

(जी) यदि उपरोक्त (एफ) में दर्शाये अनुसार पत्नी/पति कहीं नौकरी में नहीं हो, तो—

ऐसे मामलों में मंडल का कर्मचारी निम्न प्रमाण पत्र देगा —

“प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिसके लिए मैंने अवकाश यात्रा सुविधा का दावा किया है, वह किसी भी ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम स्वायत्त संस्था की नौकरी में नहीं है जिसे केन्द्र सरकार स्थानिक संस्था की संपूर्ण या आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त है, और जो अपने कर्मचारी और उसके परिवारों को अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान करते हैं।”

(एच) पति-पत्नी दोनों यदि मंडल के कर्मचारी हों, तो—
पति या पत्नी एक दूसरे के परिवार सदस्य के रूप में यात्रा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह तभी लागू होगा, जब पति और पत्नी साथ रहते हों। यदि किसी कारण वे अलग रहते हों, तो वे अपनी-अपनी पात्रता के अनुसार दो भिन्न कर्मचारियों की तरह सुविधा स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

(आई) परिवार के लिए स्वतंत्र रूप से सुविधा मांगी जा सकती है—जहां मंडल का कर्मचारी और उसका परिवार अलग-अलग यात्रा करते हैं, तो कर्मचारी द्वारा स्वतंत्र रूप से दावा प्रस्तुत किए जाने में मंडल को कोई आपत्ति नहीं है।

(जे) मूल निवास स्थान के बदले अन्य स्थान पर अध्ययन कर रहे बच्चे—

मंडल के कर्मचारी के बच्चे जो पूर्ण रूप से उनके उपर निर्भर हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए उनसे दूर हॉस्टेल में रह रहे हैं, वे कर्मचारी के परिवार के सदस्य होने के नाते मूल निवास स्थान एवं भारत

के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनके मामले में—(i) अध्ययन स्थान से मूल निवास स्थान/या भारत के किसी स्थान तक और वहां से अध्ययन स्थान पर वापसी का किराया, और (ii) कर्मचारी के मंडल में नौकरी के स्थान से मूल निवास स्थान/या भारत के किसी स्थान तक और वहां से वापसी यात्रा का किराया इन दोनों में जो किराया राशि कम होगी, उस राशि की प्रति-पूर्ति की जाएगी।

(के) मंडल के अविवाहित कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा सुविधा लाभ—

मंडल के ऐसे अविवाहित कर्मचारी जिनके निर्भर माता-पिता, बहन तथा नाबालिग भाई जो उनके मूल निवास स्थान में रहते हैं, उन कर्मचारियों को भी प्रत्येक वर्ष मूल निवास स्थान जाने के लिए अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। यह सुविधा मंडल के कर्मचारी, माता-पिता, बहन और नाबालिग भाईयों को देय अन्य सारी अवकाश यात्रा सुविधाओं के बदले में प्राप्त होगी।

(एल) कर्मचारी की पत्नी व बच्चों से संबंधित अवकाश यात्रा सुविधा की देय और छोड़ने की शर्तें—

यदि मंडल के कर्मचारी का पति/पत्नी व निर्भर बच्चे उसकी नौकरी के स्थान से अन्य स्थान पर रहते हैं, तो उन मामलों में परिवार सदस्यों को दो वर्षीय फंड में एक बार उनके रहने के स्थान से मूल निवास स्थान की एवं चार वर्ष के फंड में एक बार भारत के किसी भी स्थान की अवकाश यात्रा सुविधा दी जा सकती है, लेकिन देय प्रति-पूर्ति की राशि—परिवार द्वारा प्रत्यक्ष तय किये गये अंतर का किराया अथवा मुंबई और किसी भारतीय स्थान/मूल निवास स्थान के बीच के अंतर का किराया—इनमें से जो कम है, उस किराये राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

7. मूल निवास स्थान

“मूल निवास स्थान” अर्थात् (i) कर्मचारी का स्थायी निवास स्थान या गांव, जो उसकी सेवापंजी या संबंधित कर्मचारी के अन्य उचित रेकार्ड में बताया गया है या (ii) उचित कारण देकर (जैसे जहां उसकी अचल संपत्ति है या उसका नजदीकी रिश्तेदार जैसे माता-पिता, भाई का स्थायी निवास उसके द्वारा घोषित अन्य कोई ऐसा स्थान जहां साधारणतः उसका वास्तव्य रहता, परंतु मंडल की नौकरी के कारण हो वहां नहीं रह पाता। कर्मचारी द्वारा घोषित निवास स्थान की

मान्यता के लिए निम्न मापदंड उपयोग में लाया जाये—

- (i) कर्मचारी द्वारा घोषित स्थान कोई ऐसा स्थान है जहाँ पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने लिए उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। यदि है, तो नौकरी में लगने के बाद भी क्या वह नियमित रूप से वहाँ जाता रहा है?
- (ii) क्या घोषित स्थान पर कर्मचारी का खुद का कोई मकान है? या वह उस स्थान पर ऐसी संपत्ति होने वाले संयुक्त परिवार का सदस्य है?
- (iii) क्या उसके कोई नजदीकी रिश्तेदारों का उस गांव/स्थान में वास्तव्य है?
- (iv) क्या मंडल की नौकरी में लगने से पहले कर्मचारी कुछ वर्ष वहाँ (मूल निवास स्थान) रहता था?

उपरोक्त मापदंडों में से एक के बाद दूसरा मापदंड तब लगाना चाहिए, जब उसके पहले वाला मापदंड पूरा नहीं हो पाता। यदि किसी कर्मचारी का, या वह जिसका सदस्य है उस परिवार का मकान या जमीन संपत्ति एक से ज्यादा जगह पर हो, तो कर्मचारी उचित कारण देते हुए कोई भी एक स्थान चुन सकता है, बशर्ते कि उसके द्वारा घोषित स्थान को “मूल निवास स्थान” के रूप में स्वीकार किया जाय अथवा नहीं, इस बात पर उसके अपने विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। जब घोषित मूल निवास स्थान की स्वीकृति का मापदंड “नजदीकी रिश्तेदार का वास्तव्य” बताया हो, तो नजदीकी रिश्तेदार का ऐसा वास्तव्य अधिकतर “स्थायी” स्वरूप का होना चाहिए।

8. (1) मूल निवास स्थान की घोषणा—

(i) हर कर्मचारी अपने “मूल” निवास स्थान की घोषणा करेगा। इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्रचलित होने वाले विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी यदि मूल निवास स्थान की घोषणा कर चुका है, तो वह मूल निवास स्थान की वह घोषणा इन विनियमों के अंतर्गत ही मानी जाएगी। मंडल की सेवा में आने वाले हर नये व्यक्ति को उसके आगमन की तिथि से छः महीनों के अंदर अपने मूल निवास स्थान की घोषणा करनी होगी।

(ii) विभाग प्रमुख के अलावा अन्य कर्मचारी के द्वारा मूल निवास स्थान के बारे में की गयी घोषणा को हर मामले में उसके विभाग प्रमुख की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। विभाग प्रमुख आवश्यक होने पर उचित सबूत मंगवाकर संबंधित घोषणा की सत्यता परख सकते हैं। जिस तिथि को कर्मचारी द्वारा मूल निवास स्थान की घोषणा की जाती है, उसी तिथि घोषणा लागू होने की तिथि समझी जाएगी—कि विभाग

प्रमुख की स्वीकृति लिखि या स्वीकृति का संदेश प्राप्त होने की तिथि। विभाग प्रमुख द्वारा की गयी “मूल निवास स्थान” की घोषणा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। कर्मचारी द्वारा की गयी तथा विभाग प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा—जैसा मिला हो (इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्रचलित विनियमों के अंतर्गत) मान्य हुई घोषणा ही स्वीकृत मानी जाएगी।

(iii) एक बार की गयी “मूल निवास स्थान” की घोषणा ही साधारण रूप से अंतिम घोषणा मानी जाएगी। परंतु अपवाद की स्थिति में विभाग प्रमुख (और विभाग प्रमुख के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) उक्त घोषणा में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान भिन्न एक ही बार किया जाएगा। प्रतिनिधुक्ति (डेप्युटेशन) पर मंडल की नौकरी में आए कर्मचारियों के मामले में घोषणा में परिवर्तन की अनुमति केवल प्रेपक प्राधिकारी (लेडिंग अथॉरिटी) के अनुमोदन के बाद ही मंजूरी की जाएगी।

(iv) निर्धारित समय के बाद की गयी मूल निवास स्थान की घोषणा विभाग प्रमुख द्वारा (और विभाग प्रमुख के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा) स्वीकार की जा सकती है। तथापि ऐसी स्वीकृति मूल निवास स्थान की घोषणा में परिवर्तन के लिए दिए जाने वाले एक मीके के बदले में दी जाएगी और वही घोषणा कर्मचारी की अंतिम घोषणा मानी जाएगी और ऐसे मामलों में मूल निवास स्थान की घोषणा में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) विभाग प्रमुख अपनी सुविधा के लिए अपने विभाग के कर्मचारियों के संबंधित मूल निवास स्थानों का रजिस्टर रख सकता है।

(2) भारत के बाहर के स्थान के लिए मूल निवास स्थान की घोषणा—

मंडल का कर्मचारी यह घोषणा कर सकता है कि उसका मूल निवास स्थान भारत के बाहर है। यदि ऐसी घोषणा के समर्थन में दिए कारणों से संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो, तो वह कर्मचारी मूल निवास स्थान की यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इस प्रकार के मामलों में मंडल की सहायता निम्न यात्राओं के किराये तक सीमित रहेगा:

(i) मूल निवास स्थान से सबसे नजदीकी (लघुतम मार्ग से) रेल स्थानक तक और वापसी का किराया।

(ii) भारत में जहाज पर चढ़ने/जहाज से उतरने के पोर्ट तक जाने/से आने का नजदीकी रेलवे स्टेशन तक का किराया उस उद्देश्य के लिए नजदीकी पत्तन (पोर्ट) या गड्डी होगा मंडल के कर्मचारी को मूल निवास स्थान से सबसे नजदीकी पोर्ट।

इच्छा से पत्राचार (पत्राचार यंत्रण) गुप्त विस्तार वगैरहों की घोषणा कर सकते हैं, और अवकाश यात्रा सुविधा के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत अपने अपने परिवार सदस्यों के संबंध में यात्रा सुविधा के लाभ के लिए अलग से दावा कर सकते हैं तथापि इसके लिए शर्त यह होगी कि यदि पति या पत्नी एक दूसरे के (पत्नी के/पति के) परिवार सदस्य के नाते यात्रा सुविधा का लाभ लेते हैं, तो उसे (पति/पत्नी को) उसके अपने लिए अलग से सुविधा लाभ देय नहीं होगा। वच्चे एक विशिष्ट खंड में दोनों में से किसी एक पालक के परिवार सदस्य के नाते अवकाश यात्रा सुविधा लेने के हकदार होंगे। अवकाश यात्रा सुविधा की देयता के लिए अन्य सभी शर्तें योजना के सामान्य प्रावधानों के अनुसार लागू होती रहेगी।

9. (रेल यात्रा में) में स्थान की श्रेणियां -

(ए) रेलवे द्वारा जोड़े गए स्थानों की यात्रा -

(i) जब कर्मचारी रेलवे द्वारा यात्रा करता है, तब उसे निम्न प्रकार की श्रेणियों का किराया देय होगा -

प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारी द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित टुटायर स्लीपर/प्रथम श्रेणी

वे कर्मचारी, जिनका वेतन 1665/- रु. या उससे अधिक है। द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित टुटायर स्लीपर/प्रथम श्रेणी

वे कर्मचारी, जिनका वेतन 1665/- रु. से कम है। द्वितीय श्रेणी

(ii) कर्मचारी और उनके परिवार को रेलवे के उसी वर्ग का किराया देय होगा जिसके लिए वह यात्रा के प्रत्यक्ष समय हकदार है। कर्मचारी या उसके परिवार या दोनों को उनके देय वर्ग में ऊपरी दर्जे या निम्न दर्जे में यात्रा करने की अनुमति है। मंडल की जिम्मेदारी देय श्रेणी का किराया या वास्तविक खर्च, इन दोनों में जो कम है, उसके भुगतान की रहेगी।

(iii) (ए) कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य अवकाश यात्रा सुविधा के साथ रेलवे प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रियायती वापसी यात्रा टिकट (जैसे मिजनल छूट, छात्र छूट आदि) का लाभ प्राप्त कर सकता है, जो इस प्रकार के रियायती टिकट का इस्तेमाल करते समय देय श्रेणी से उच्च या निम्न श्रेणी के वर्ग से यात्रा करने की अनुमति होगी।

(बी) जहां कर्मचारी और/अथवा उसका परिवार अवकाश यात्रा सुविधा के साथ रेल प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली रियायती सक्क्यूलर यात्रा टिकट का लाभ उठाना है, वहां कर्मचारी को मुंबई और मूल निवास स्थान के बीच लघुतम मार्ग से यात्रा के लिए सामान्य दर से देय श्रेणी की किराया राशि/प्रत्यक्ष व्यय राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। चार वर्षीय खंड में एक बार भारत के किसी स्थान की यात्रा अगर रियायती सक्क्यूलर टिकट से की हो, तो मुंबई और उस स्थान के बीच की लघुतम मार्ग से यात्रा के लिए

रेल श्रेणी का प्राधान्य रूप से निर्दिष्ट पत्राचार पत्राचार शुल्क - इसमें से जो राशि कम होगी, उतनी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) जो कर्मचारी साधारण रूप से प्रथम वर्ग से यात्रा के लिए पात्र है, वह यात्रा सुविधा का लाभ लेने समय डीलक्स वातानुकूलित रेल के दूसरे वर्ग में यात्रा कर सकता है।

(v) जब कर्मचारी या उसका कोई परिवार सदस्य लम्बे मार्ग से (जो सबसे सस्ता नहीं है) और रेलवे की दो भिन्न श्रेणियों में - जैसे कुछ यात्रा प्रथम वर्ग में - जिसके लिए वह हकदार है, और कुछ दूसरे वर्ग में - करता है, तो जिस श्रेणी के लिए वह हकदार है, उस श्रेणी का पूरे अंतर का किराया और वास्तव्य खर्च - दोनों में जो कम है, उतनी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vi) कर्मचारी या उसका परिवार या दोनों रेलवे द्वारा जोड़े गए स्थानों के बीच हवाई जहाज या रोड या स्टीमर से यात्रा करते हैं, तो ऐसे मामलों में खर्च के लिए मंडल की सहायता निम्न राशि तक सीमित होगी - i) कर्मचारी या उसका परिवार यदि रेल से यात्रा करते तो देय श्रेणी की किराया राशि, अथवा (ii) प्रत्यक्ष खर्च की राशि - इन दोनों में से जो राशि कम हो।

(vii) अवकाश यात्रा सुविधा लेने समय राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा की गयी यात्रा के संबंध में देयता -

वेतन श्रेणी	देय वर्ग
(ए) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	द्वितीय वर्ग वातानुकूलित टुटायर स्लीपर
(बी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनका वेतन रु. 2405/- और उससे अधिक है।	—
(सी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनका वेतन रु. 1665/- और उससे अधिक लेकिन 2405/- रु. से कम है।	वातानुकूलित कुर्सीयान
(डी) जिनका वेतन 1665/- से कम है।	तय किए गए अंतर लिए किसी अन्य गाड़ी के दूसरे वर्ग का जो किराया होगा, उतनी ही राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(बी) रेल से न जुड़े स्थानों की यात्रा -

(i) पथ (रोड) द्वारा :

जहां ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें दो निश्चित स्थानों के बीच नियमित कालांतर से वाहन आते-जाते हैं, और उसके लिए निर्धारित दर से किराया

उचित जगह से यात्रा करें :-

- (ए) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के किमी भी प्रकार की बस अधिकारी
- (बी) कर्मचारी जिनका वेतन 1665/- रु. या उससे अधिक है।
- (सी) कर्मचारी जिनका वेतन 1665/- रु. से कम है। सामान्य बस द्वारा ही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यदि उक्त सामान्य बस में जगह न प्राप्त होने पर एक्सप्रेस बस में भी यात्रा कर सकते हैं।

उपरोक्त 12 वय के बच्चा के लिए किराया आगे दर से देय होगा।

(ii) हवाई जहाज द्वारा यात्रा :-

जो स्थान रेलवे से जुड़े नहीं हैं और वहां यात्रा की, तो अन्य कोई सुविधा या तो उपलब्ध नहीं है, या है, तो वह अधिक मंहगी है, तो उन मामलों में मंडल का कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है।

(सी) पोर्ट ब्लेयर की यात्रा :-

जहाज पर चढ़ने के स्थान (पोर्ट) तक की यात्रा का सर्वसाधारण पद्धति से ही नियमन होगा। जहाज पर चढ़ने के पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए देयता निम्न प्रकार है :

मूल वेतन	एम. वी. अकबर	एम. वी. मजीद	अन्य
(ए) सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी	संलग्न प्रसाधनगृह सहित डीप्टी वर्ग	प्रथम श्रेणी	डीलक्स केबिन
(बी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 2405/- रु. और उससे अधिक है	---	---	I श्रेणी केबिन
(सी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 1665/- रु. या उससे अधिक लेकिन 2405/- रु. से कम	प्रथम श्रेणी का कमरा सार्वजनिक प्रसाधन गृह	---	I श्रेणी केबिन
(डी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 1405/- रु. से अधिक लेकिन 1665/- रु. से कम	वातानुकूलित शयनागार वर्ग	दूसरी श्रेणी के कमरे	II श्रेणी "ए" केबिन
(इ) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 1405/- रु. से कम है।	वातानुकूलित शयनागार वर्ग	मोफा	II श्रेणी 'बी' केबिन
(एफ) सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	बंक बलास	फर्श/जमीन पर बैठक	बंक बलास

(डी) स्टीमर या समुद्री यात्रा के संबंध में देयता

काश यात्रा सुविधा के लिए स्वीकार्य नहीं है :--

- मूल वेतन देय श्रेणी
- (ए) सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी उच्चतम श्रेणी/वर्ग
- (बी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 2405/- रु. और उससे अधिक है। ---"
- (सी) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 1665/- रु. से ऊपर लेकिन 2405/- रु. से कम है। यदि दो वर्ग हैं, तो निम्न श्रेणी और दो से अधिक वर्ग हैं, तो बीच वाला वर्ग या दूसरा वर्ग
- (डी) तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनका वेतन 1405/- रु. के ऊपर लेकिन 1665/- रुपये से कम है। यदि दो वर्ग हैं, तो निम्न श्रेणी और दो से अधिक वर्ग हैं, तो बीच वाला वर्ग या दूसरा वर्ग
- (इ) तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनका वेतन 1405/- रु. से कम है। यदि चार वर्ग हैं, तो तीसरा वर्ग।
- (एफ) सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबसे न्यूनतम वर्ग।
- (इ) निम्न प्रकार के वाहनों द्वारा की गई यात्रा अव-

(ए) प्राइवेट चार्टर्ड वाहन - इनमें वे वाहन भी शामिल हैं, जो प्राइवेट पार्टियां सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्यटन विकास निगम या राज्य परिवहन निगम अथवा स्थानीय निकायों (बॉडिज) के परिवहन उपक्रम से किराये पर लेनी हैं और चार्टर पर चलती हैं।

(बी) मुपोट्ट कर्मचारियों खुद के, उधार लिए या किराये पर लिए गए वाहन तथापि, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य सरकार की अनुमति से नियमित परिवहन सेवा के रूप में चलायी जाने वाली बसों में - जो नियमित कालांतर के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना होती हैं और जिनका किराया निर्धारित दर के अनुसार लगाया जाता है - की गयी यात्रा व्यक्तिगत बस से की गई यात्रा नहीं मानी जाती। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए अवकाश बस की यात्रा केवल उन्हीं मामलों में स्वीकार होगी, जहां यात्रा पूर्णतः आयटीडीसी/राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ही या तो उनकी अपनी बसों में संचालित/प्रायोजित की गई हो, या आयटीडीसी/राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह यात्रा वास्तव में उनके द्वारा संचालित/प्रायोजित की गई थी - निजी व्यक्तियों/पार्टी द्वारा नहीं।

(एफ) भ्रूल (सरफेस) परिवहन यदि कुछ अस्थायी समय के लिए अस्त-मस्त/बंद हो, तो उसे "पर्यायी यात्रा-साधन का उपलब्ध न होना" नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के मामलों में प्रतिपूर्ति या रेलयात्रा के लिए देय श्रेणी के किराये तक सीमित रहेगी।

(जी) जहां पति और पत्नी दोनों मंडल के कर्मचारी हैं, वहां उनके परिवार को उक्त सुविधा सिर्फ पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को देय श्रेणी से दी जाएगी—दोनों को नहीं।

(एच) (ए) सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आरक्षित स्थानों में की गयी यात्रा के लिए रेलवे द्वारा लगाये गये विशेष पूरक प्रभार की अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत उसी प्रकार प्रतिपूर्ति योग्य होंगे जिस प्रकार रेल किराये की राशि होती है।

(बी) आरक्षण के लिए दी गयी प्रतिरिक्त प्रभार राशि भी मंडल द्वारा बहुत की जाएगी।

(सी) अवकाश यात्रा सुविधा लेते हुए की गयी यात्राओं के मामलों में गाड़ी की शायिका के आरक्षण के लिए किए गए तारके, रेलवे को भरा किए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(डी) उक्त सुविधा के अंतर्गत किए गए अन्य आकस्मिक खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(आय) लघुतम मार्ग पर आधारित सुविधा—

(ए) कर्मचारी द्वारा मुंबई से भारत के किसी स्थान या मूल निवास स्थान तक की गयी यात्रा के लिए मंडल की तरफ से वह रेल किराया राशि देय होगी, जो "थ्रू" टिकट पर आधारित तय किए लघुतम मार्ग के किराये की राशि होगी। कर्मचारी या उसका परिवार भारत के किसी स्थान या मूल निवास स्थान—जैसा मामला हो—तक जाते या जाँटते समय किसी भी मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन मंडल की सहायता उपरोक्त के अनुसार दिए किराये तक सीमित रहेंगे। यदि दुर्घटना या अन्य किसी कारण से लघुतम मार्ग उपलब्ध नहीं/बंद हो, तो यात्रा के प्रत्यक्ष मार्ग के किराये की प्रतिपूर्ति देने का अधिकार विभाग प्रमुख का रहेगा।

(बी) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक मार्ग/वाहन उपलब्ध हैं, उदाहरण: जहां दो स्थान जोड़ने वाला सीधी बस सेवा भी है, लंबे मार्ग से जाने वाला बस भी है और अन्य सार्वजनिक वाहन भी उपलब्ध हैं—और यदि लघुतम सुलभ मार्ग निश्चित करने में कोई संविधता या कठिनाई होती है, तो स्थानांतर यात्राओं के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया गया अंतर स्वीकार किया जाए।

स्पष्टीकरण:

"लघुतम अंतर का अर्थ यहाँ वही होगा जो कार्यालयीन काम से की गयी यात्रा के संबंध में स्वीकार्य है।

(जे) मूल निवास स्थान के लिए बेटेड माइलेज यात्रा—

संपूर्ण अवकाश यात्रा या आंशिक यात्रा के लिए कर्मचारी को यदि गृहित (अयुम्ड) या बेटेड माइलेज पर आधारित दर से (जैसे—कालका सिमला विभाग) या स्कीत (इनकलेटेड) दर से (जैसे—सितीगुड़ी-राजिलिंग विभाग) किराया देना पड़ता है, और यदि रेलवे द्वारा तय किए गए पूरे अंतर का किराया (गृहित या बेटेड माइलेज पर आधारित प्रथम स्कीत दर से भरा किया गया—जैसा मामला हो—किराया सम्मिलित करके) आंशिक अंतर के लिए सामान्य दरों से लागू किराये से अधिक है, तो—मुंबई और यात्रा स्थान अथवा मूल निवास स्थान—(जैसा मामला हो) के बीच का प्रत्यक्ष अंतर चाहे जितना भी हो, संबंधित कर्मचारी अवकाश के दौरान यात्रा सुविधा का हकदार होगा। इस प्रकार के मामले में मंडल द्वारा कर्मचारी को देय प्रतिपूर्ति की रकम होगी—(i) मुंबई से कर्मचारी के मूल निवास स्थान या यात्रा स्थान (जैसा मामला हो) तक का वास्तविक रेल किराया (यात्री-कर सम्मिलित करके) और (ii) मुंबई से साधारण दर से लागू होते वाला किराया (यात्री-कर सम्मिलित करके)—इन दोनों किरायों के फर्क की राशि यह व्यवस्था प्रदान-वापसी दोनों यात्राओं के संबंध में लागू है।

टिप्पणी:—जब-जब वेतन श्रेणी में सुधार होगा, तब-तब इस विनियम में निर्धारित अवकाश यात्रा सुविधा की देय राशि में भी उसके अनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

10. (यात्रा) सुविधा केवल भारत के स्थानों तक सीमित है:

(ए) भारत के किसी भी स्थान से तत्पर्य है वह स्थान जो भारत की सीमाओं के अंदर है—किर चाहे वह भारत की मूल भूमि पर हो या समुद्रीपार और वह पूर्ण-रूप से रेल द्वारा जोड़ा हो। अंशतः रेल से और अंशतः रोड़ या स्ट्रमर सेवा द्वारा जोड़ा हो। पर वह आंशिक हिस्सा रेल द्वारा जुड़ा न हो। भारत के किसी भी स्थान में मंडल के कर्मचारी का मूल निवास स्थान भी शामिल है।

(बी) जब मंडल का कर्मचारी और/अथवा उसके परिवार का/के सदस्य भारत के किसी भी स्थान को यात्रा के लिए उक्त सुविधा प्राप्त करना चाहता/चाहते हो, तब विभाग प्रमुख को यात्रा का स्थान जाने से पहले सूचित किया जाना चाहिए।

(सी) अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए मंडल के कर्मचारी और/या उसके परिवार सदस्य/सदस्यों की अपने द्वारा घोषित स्थानों की ही यात्रा करनी चाहिए। घोषित स्थानों की यात्रा किसी भी मार्ग द्वारा की जा सकती है लेकिन अवकाश यात्रा सुविधा के बाबे का नियमन घोषित स्थान व नौकरी के स्थान के बीच के "थ्रू" टिकट के आधार पर निर्धारित सीधे सवुतम मार्ग (के किराये) के अनुसार ही किया जाएगा।

(डी) विभाग प्रमुख की अनुमति से और विभाग प्रमुख के मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की मंजूरी से घोषित स्थानों में परिवर्तन यात्रा शुरू करने के पहले किया जा सकता है, लेकिन यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

अपवाद :

(ए) अगर यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर होने वाली स्थितियों के कारण स्थान-परिवर्तन का अनुरोध यात्रा शुरू होने से पहले करना असंभव था, तो ऐसी परिस्थिति में विभाग प्रमुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा उक्त शर्त शिथिल की जा सकती है और दावा मान्य किया जा सकता है।

(बी) यदि मंडल का कर्मचारी 4 वर्षीय खंड से संबंधित अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेते हुए घोषित स्थान की यात्रा के लिए प्रस्थान कर देता है और कुछ अनिवार्य परिस्थिति के कारण रास्ते में ही किसी स्थान पर रुक जाता है, और घोषित स्थान की यात्रा नहीं कर पाता, तो उसका दावा मंजूर किया जाए, परंतु कि वह बीच का स्थान उसके द्वारा घोषित गन्तव्य स्थान के मार्ग पर ही हो।

11. छुट्टी का प्रकार—

(1) साधारण/आकस्मिक/विशेष आकस्मिक या प्रसूति छुट्टियों के दौरान की गई यात्राओं के लिए कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा पाने का अधिकारी है। फिर छुट्टी की अवधि चाहे कितनी भी हो। यदि कोई कर्मचारी साधारण/आकस्मिक/विशेष आकस्मिक या प्रसूति छुट्टी पर जाता है और नौकरी पर वापस आए बिना त्यागपत्र दे देता है, तो वह कर्मचारी उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा। परंतु उपरोक्त शर्त कर्मचारी के परिवार सदस्यों को लागू नहीं होगी।

(2) इनडोअर कर्मचारियों के मामले में अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ केवल रविवार, वैकल्पिक छुट्टी या अन्य छुट्टी की ही अवधि के दौरान (जिसमें दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है) ही नहीं लिया जा सकता (अर्थात् छुट्टियों के अलावा स्वयं अपना कोई अवकाश लेना आवश्यक है)।

(3) निवृत्तिपूर्व की छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी के दौरान की गयी यात्रा के संबंध में कर्मचारी और उसके परिवार सदस्यों को यात्रा सुविधा केवल मुंबई से प्रस्थान यात्रा के लिए ही देय होगी, बशर्ते कि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के संबंधित खंड में उक्त (यात्रा) सुविधा पहले ही न ले चुका हो। ऐसे मामले में कर्मचारी और उसका परिवार—दोनों की यात्रा अवकाश के दौरान ही प्रारंभ होनी चाहिए।

(4) कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य या दोनों उस सुविधा के हकदार होंगे—फिर मूल निवास स्थान में टहलने की प्रत्यक्ष अवधि चाहे जो भी हो।

12. (1) दावों की प्रस्तुति की रीति :

मूल निवास स्थान या चार वर्ष के खंड में एक बार भारत के किसी भी स्थल की यात्रा के खर्च की नगद प्रतिपूर्ति निम्न कागजात प्रस्तुत करने के उपरान्त की जाएगी

(i) यात्रा बिल के प्रपत्र में लिखित दावा, और (ii) आय प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित होगा कि उन्होंने ऐसी यात्राएं वास्तविक रूप से की हैं, और जिस वर्ग के किराये की प्रतिपूर्ति की मांग की है, उस वर्ग में ही यात्रा की है—निम्न वर्ग में नहीं।

(2) निर्धारित प्रमाणपत्र :

यात्रा सुविधा के लिए यात्रा भत्ते के बिल के साथ लेखा अधिकारी को दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। एक संबंधित विभाग प्रमुख से और दूसरे कर्मचारी की तरफ से, जहां तक संभव हो, सके, ये प्रमाणपत्र परिशिष्ट 1 और 2 में दशमि के अनुसार होंगे।

(3) अनिवार्य प्रमाण :

जिस यात्रा सुविधा के लिए इन विनियमों के अंतर्गत सहायता का दावा किया है, वह यात्रा प्रारंभ करने से पहले कर्मचारी अपने विभाग प्रमुख अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी को उस यात्रा की सूचना देगा। साथ ही, कर्मचारी को उसने वह यात्रा वास्तव में की है, इस बात का लेखाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रमाण जैसे—रेल टिकटों की क्रम संख्या, नगद रसीदें आदि भी प्रस्तुत करना होगा। यदि विभाग प्रमुख और विभाग प्रमुख के मामले में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष—बाबे की सच्चाई और यात्रा वास्तव में की गई। इसका प्रमाण से अन्यथा संतुष्ट हो, तो वे रेल टिकट क्रमांक अथवा रेल टिकटों की नगद रसीदों की प्रस्तुति करना, इन विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी, उसके परिवार अथवा इन दोनों के द्वारा यात्रा प्रारंभ करने से पहले विभाग प्रमुखों को पूर्व-सूचना देना आदि के संबंध में कुछ मामूली छूट दे सकते हैं।

13. सहायता रिकार्ड : इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई सारी सहायता का उचित रिकार्ड रखा जाएगा। यह रिकार्ड सेवापंजी में प्रविष्टि अथवा अन्य उचित रिकार्ड के रूप में रखा जाएगा तथा उस रिकार्ड में की गई यात्रा/यात्राओं की आरंभ की तिथि/तिथियां दर्शाई जाएगी। जिस प्राधिकारी पर सेवापंजी रखने की जिम्मेदारी है, वह प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी कर्मचारी छुट्टी पर जाता है और यात्रा सुविधा का लाभ लेता है, तो यह तथ्य रिकार्ड में दर्शाया जा रहा है।

14. पेशगी : कर्मचारी यात्रा सुविधा का लाभ उठा सके, इस दृष्टि से कुछ पेशगी निम्न शर्तों पर दी जा सकती है— जैसे :—

- (ए) हर मामले में पेशगी की राशि सीमित की जाएगी आने और जाने—दोनों निम्न प्रकार की यात्राओं के खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में मंडल को जिस राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी उस अनुमानित राशि के 90 प्रतिशत।
- (बी) कर्मचारी और उसके परिवार सदस्य यात्रा सुविधा का लाभ स्वतंत्र रूप से अर्थात् अलग-अलग समय लेते हैं, तो देय पेशगी राशि भी अलग से ली जा सकती है और दावों का समायोजन भी अलग से किया जा सकता है। तथापि जिस मामले में कर्मचारी द्वारा अपने परिवार सदस्यों के संबंध में समेकित (कम्पोलिडेड) पेशगी ली जाती है, वहां दावों का समायोजन एक ही बिल में किया जाएगा।
- (सी) कर्मचारी, उसके परिवार के सदस्य या दोनों की आने और जाने—दोनों समय की यात्राओं के लिए पेशगी राशि प्रस्थान यात्रा के समय ली जा सकती है, बशर्ते कि कर्मचारी की अवकाश अवधि अथवा उसके परिवार के सदस्यों की अपेक्षित अनुपस्थिति अवधि 90 दिनों से अधिक न हो। जहां अवकाश अवधि या अपेक्षित अनुपस्थिति की अवधि कथित सीमा से अधिक है, उस मामले में पेशगी केवल प्रस्थान यात्रा के लिए ली जाय। अगर प्रस्थान और वापसी—दोनों यात्राओं के लिए पेशगी ली गई हो और बाद में यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी अथवा उसके परिवार की मुंबई में अनुपस्थिति की अवधि कथित सीमा से अधिक होने की संभावना है, तो कर्मचारी को पेशगी की आधी राशि तुरंत मंडल को लौटानी होगी।
- (डी) अस्थायी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए पेशगी तभी मंजूर की जाएगी जब वे किसी स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति (व्यॉरिटी) प्रस्तुत करेंगे। यह बात उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी,

जिनोंने पांच वर्ष से अधिक अविरत सेवा की हो।

- (इ) यदि प्रस्थान यात्रा पेशगी प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर आरंभ नहीं की जाती है, तो पेशगी की पूर्ण राशि तुरंत लौटानी होगी। सभी मामलों में पेशगी प्राप्त करने के 10 दिन के अंदर-अंदर कर्मचारी को रेल या बस यात्रा का टिकट आदि पेश करना होगा।
- (एफ) ली गयी पेशगी के साथ भत्ते के दावे का समायोजन वापसी यात्रा पूरी करने के एक महीने के अंदर किया जाना चाहिए और यदि पेशगी न ली हो, तो समायोजन तीन महीनों के अंदर किया जाना चाहिए।
- (जी) छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ते के संबंध में ली गयी पेशगी का हिसाब यात्रा पूरी होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाय जिस प्रकार दोरे के लिए ली गयी यात्रा-भत्ता पेशगी का दिया जाता है।
- (एच) लेखा अधिकारी द्वारा रखी गयी उचित पंजियों द्वारा पेशगी के समायोजन का निरीक्षण होगा।
- (आई) जहां मंडल के कर्मचारी द्वारा पेशगी ली गयी है, वहां कर्मचारी द्वारा यात्रा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा वापसी यात्रा के एक महीने के अंदर पेश किया जाएगा। यदि मंडल का कर्मचारी ऐसा नहीं करता, तो उसे पेशगी की पूरी राशि तुरंत एक मुश्त राशि के रूप में लौटानी होगी। उक्त का यसूली किस्तों में करने का कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा।
- (जे) यदि पेशगी की मंजूरी के लिए रखी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं होता या अवकाश यात्रा सुविधा के लिए पेशगी मंजूर करने के नियमों को भंग किया जाता है, तो विभाग प्रमुख पेशगी पं: दंड के रूप में ब्याज लगावेगा, यह ब्याज—वाहन (मोटर कार छोड़कर) की खरीद के लिए दी जाने वाली पेशगी के ब्याज के दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक होगा।
- (के) यदि कर्मचारी प्रतिनिधित्व पर है और प्रत्यावर्तन (रिवर्सन) होने के तुरंत बाद लेकिन मूल विभाग में वापसी के पहले अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त करता है, तो उस मामले में उसे प्रति निवृत्ति पर लेनेवाला (बॉरोइंग) विभाग मूल विभाग से परामर्श करने के पश्चात पेशगी मंजूर कर सकता है। इस स्थिति में संबंधित कागजातों की एक प्रति उसके मूल विभाग को भेजी जाएगी, ताकि मूल विभाग उक्त पेशगी के समायोजन संबंधी काम की देख रेख करें।

15. लेखाशीर्ष : यात्रा सुविधा भत्तों पर किया गया खर्च संबंधित लागत केन्द्रों में टाइप, 530 "अवकाश यात्रा सुविधा" के अंतर्गत नामे (ड्रिबिट) किया जाएगा।

16. अर्थ निर्णय : किसी भी कर्मचारी पर इन विनियमों का लागू होना अथवा उनके अर्थ निर्णय के बारे में संदिग्धता हो, तो उस संदर्भ में अध्यक्ष जो की निर्णय अंतिम निर्णय होगा। परन्तु अध्यक्षजी के निर्णय से व्यक्ति कर्मचारी उनके आदेश मिलने के साठ दिनों के अंदर विश्वस्त मंडल को पुनरावेदन (या निवेदन) प्रस्तुत कर सकते हैं और विश्वस्त मंडल उस पर अपना योग्य निर्णय दे।

17. रद्द करना और बनाए रखना : इन विनियमों के अनुरूप और इन विनियमों के आरंभ से तुरंत पहले प्रवर्तित सभी आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

बशर्ते कि इस प्रकार रद्द किए गए विनियमों के अंतर्गत बिंदु गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आदेश कार्यवाही इन नए विनियमों के अनुरूप प्रावधानों के अंतर्गत ही दिशा गया था/वह कार्यवाही इन विनियमों के अंतर्गत की गई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1992

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust Employees (Leave Travel Concession) (Amendment) Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Bombay and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PP-12016/29/91-PE. I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

THE BOMBAY PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) AMENDMENT REGULATIONS, 1992

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the existing regulations on the subject, the Board of Trustees of the Port of Bombay, with the approval of the Central Government, as required by sub-section (1) of Section 124 of the said Act, hereby makes the following regulations, the same having been previously published in two successive issues of the Official Gazette, as required under sub-section (2) of the said Section 124, namely :

Substitute the existing regulations Nos. 1 to 27 by the following :

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the "Bombay Port Trust Employees (Leave Travel concession) Amendment Regulations, 1992".

(2) They shall come into force from the date of publication of Government's sanction in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (1) Board, Chairman, Deputy Chairman and Head of a Department have the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963).
- (2) Accounts Officer means the FA and CAO of the Board and also any other officer(s) from the Accounts Department of the Board, designated by the FA and CAO, to regulate claims of employees under these regulations.
- (3) Concession means the leave travel concession admissible under these regulations.
- (4) Employee means an employee of the Board.
- (5) A place in India will cover any place within the territory of India, whether it is on mainland India or overseas.
- (6) Shortest direct route shall have the same meaning as given in Supplementary Rule 30 and orders issued thereunder from time to time.
- (7) The expression once in a period of two financial years means once in each block of two financial years starting from the financial year 1975-76.
- (8) The expression once in a period of four financial years means once in each block of four financial years starting from the financial year 1975-76.

3. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the concession is admissible to the Board's employees including—

- (a) 'B' Category Shore Workers; and
- (b) Contract employees

Every employee appointed on contract basis shall be eligible for the concession on completion of one year's continuous service, if the period of contract is more than one year. Where the initial contract is for one year but is later extended, the total duration of the contract shall be taken into account for this purpose.

The grant of the concession to employees on contract shall be subject to the condition :

- (i) that the successive blocks of two years, or the successive blocks of four years, in the case of such employees shall be reckoned from the actual dates of their joining posts under the Board ;
- (ii) that the appropriate administrative authority certifies at the time the employee concerned avails himself of the concession that he is likely to serve under the Board for a period of two years or four years, as the case may be, from the date of his joining a post under the Board. The admissibility of the concession during the subsequent two year period, or four year period, as the case may be, will also be subject to similar conditions.

(c) Retired employee re-employed

Retired employees who are reemployed are eligible for the concession on completion of one year's continuous service subject to the conditions laid down in regulation (b) above. But in the case of re-employment immediately after retirement the period of re-employed service may be treated as continuous with the previous service for the purpose of this concession and the concession allowed for the re-employed period (provided that the concession would have been admissible to the employee had he not retired).

(d) Persons who are employed under a State Government/Central Government/Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking and are on deputation to Bombay Port Trust.

(2) The concession is not admissible to—

- (a) employees of the Railway Department and the loco and wagon establishments of the Mechanical Engineering Department who are eligible for Free Passes and/or Privilege Ticket Orders under the terms and conditions governing their service;
- (b) employees of Railway Department and the Railway Engineering Section of the Civil Engineering Department who are in receipt of a monthly special Travelling Allowance in lieu of Free Passes and/or Privilege Ticket Orders formerly admissible to them ;
- (c) Persons not in the whole time employ of the Board ; or
- (d) Persons paid from contingencies.

(3) The concession is not admissible to an employee who has not completed one year of continuous service on the date of the journey performed by him, or his family as the case may be. The condition of one year's continuous service on the date of the journey for admissibility of the concession is applicable equally to permanent employees and probationers as well as the temporary and officiating employees.

Note :

- (a) The Board's employee under suspension cannot avail of LTC as he cannot get any leave including casual leave during the period of suspension. As the continues to be in service during the period of suspension, members of his family are entitled to LTC.
- (b) LTC to officers deputed to Port Trust—
The travel concession will automatically be admissible to officers who have come on deputation to Port Trust; it will be necessary to accord a specific sanction in this regard.
- (c) Any changes brought about in the Central Civil Services LTC Rules shall mutatis mutandis be made applicable with effect from the same date to the Port Trust employees with the approval of the Board.

4. Frequency of entitlement.—(1) The concession shall be admissible to an employee once in a period of two financial years for journey to his home town and once a period of four financial years for journeys to any place in India. It shall cover the employees and their families.

(2) An employee who has a family living away from his place of work may, instead of having the concession for his family as well as for himself once in a block of two financial years, avail of the concession for himself alone once in every year during each block for visiting his home town.

Explanation :

The term 'once in a period of two financial years' means once in each block of two financial years commencing from the financial year 1975-76.

The term 'once in a period of four financial years' means once in each block of four financial years, commencing from the financial year 1975-76.

(3) The employees and their families who are unable to avail themselves of the concession in a block of two years, or in a block of four years, as the case may be, may be permitted to avail of the concession before the end of the first year of the next block of two years or before the end of the first year of the next block of four years, as the case may be.

(4) In the event of the return journey, falling in the succeeding financial year, the concession shall be counted against the financial year in which the outward journey had commenced.

5. Entitlement.—(1) All employees shall be entitled to the concession for visiting 'Home-Town' once in a block of two years and any place in India once in a block of four years.

(2) The Board shall meet the actual fares in full. There shall be no objection to an employee travelling in a lower or higher class but the Board's liability for concession shall be limited to the fares of the accommodation by the entitled class or the lower class actually used.

(3) An employee who is entitled to the concession for journeys to his 'home town' will also be entitled to the concession for journeys to any place in India once in a block of four years, however, if the concession for journeys to any place in India once in a block of four years is utilised it will be in lieu of, and adjusted against, the concession for visiting the 'home town' including the concession, if any, carried forward under sub-regulation (3) of regulation 4, to which he may be entitled at the time of journey to any place of India is undertaken. Further, such an employee will be entitled to carry forward the concession to the first year of the next block of four years, only if he is entitled to a carry forward concession to 'home town' for that year.

(4) In every case, the journey should be 'home town' and back and the claim should be for both outward and inward journeys. The journey to 'home town' need not necessarily commence from, or at, Bombay either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between Bombay and the 'home town' of the employee.

6. Definition of family :

(a) The term 'family' shall be interpreted in the same manner as in Supplementary Rule 2(8), as amended from time to time of the Posts and Telegraphs Compilation of the Fundamental Rules and Supplementary Rules for the purpose of travelling allowance on transfer. Where both the husband and wife are employees, the concession shall be admissible to the family on the scale admissible to the husband or wife and not both.

(b) Employees and Family Independent Units—

The family members need not accompany the Board's employees or even travel in the same financial year in which the Board's employee travels. The family members will get the concession independently whether the Board's employee avail it or not. The members of the family may either travel together or separately in different groups, as may be convenient to them. Where they travel in different groups at different times, reimbursement of expenditure may be allowed in respect of each group, provided the journey is performed during the currency of the block in respect of which the first group performed its journey. The return journey of each group must be completed within six months from the date of commencement of the outward journey by that group. This condition may be relaxed in special cases by the Heads of Departments, and in the case of a Head of Department by the Dy. Chairman or Chairman.

(c) Board's employee and/or member(s) can visit home town or any place in India in the same block :

In the same block of years, some members of the family can avail the concession to visit hometown, while others for visiting 'any place in India'.

(d) Board's employee and/or member(s) of family may visit the same or different places :

While availing the concession to visit 'any place in India', the Board's employee and/or member(s) of his family may visit the same place or different places of their choice.

(e) Concession for one way journey :

The concession is admissible to the members of a Board's employee's family with reference to the facts existing at the time of forward and return journey independently.

Explanations :

(A) Entitled to reimbursement in respect of the OUTWARD journey only—

(i) A dependent son/daughter getting employment or getting married after going to hometown or remaining there or prosecution of studies ;

- (ii) The family having performed the journey to home town have no intention of completing the return journey from home town, provided the Board's employee foregoes, in writing, the concession in respect of the return journey if performed by the family members at a subsequent date.

(B) Entitled to reimbursement in respect of the RETURN journey only—

- (i) A newly married husband/wife coming from home town to head quarters station or a husband/wife who has been living long at home town and did not avail of the LTC in respect of the outward journey ;
- (ii) A dependent son/daughter returning with parents or coming alone from home town where he/she has been prosecuting studies or living with grandparents etc. ;
- (iii) A child who was previously below 3 years of age but has completed three at the time of return journey ;
- (iv) A child legally adopted by a Board's employee while staying in the home town.

Note :

A child who was below 12 at the time of outward journey but has completed twelve at the time of return journey will be entitled to half fare for the outward journey and full fare for the return journey.

- (f) When the spouse of the Board's employee is employed in an office other than the Board where LTC facilities are available :

The Board's employee should furnish a certificate as under at the time of preferring the claim for LTC :

Certified that my wife/husband for whom LTC is claimed by me is employed in (name of the Public Sector Undertaking/Corporation Autonomous Body, etc.) which provides LTC facilities but he/she has not preferred and will not prefer any claim in this behalf to his/her employer.

- (g) When the spouse is not so employed as in (f) above :
The Board's employee, in such cases, should give a certificate as under ;

"Certified that my wife/husband for whom LTC is claimed by me is not employed in any Public Sector Undertaking/Corporation/Autonomous Body financed wholly or partly by the Central Government, Local Body, which provides LTC facilities to its employee and their families."

- (h) Both husband and wife are Board's employees :

In the case of husband and wife who are both Board's employees, he or she can avail of the travel concession as a family member of the other Board's employee. This condition applies only when the wife or husband is residing with the Board's employee. If, for any reason, they are residing separately, they can claim the concession independently as two separate employees according to his or her own entitlements.

- (i) Claim for family may be separate :

Where a Board's employee and his family perform journeys, separately there is no objection to his presenting separate claim.

- (j) Children prosecuting studies at places other than hometown :

Children of Board's employees wholly dependent on them but living away from them in hostels for prosecuting studies, can avail LTC as members of the Employee's family both to home town and any place in India. In their case, the claim

will be limited to the amount admissible from the place of study to hometown/any place in India and back to the place of study or from the headquarters of the Board's employee to the home town/any place in India and back, whichever is less.

- (k) Every year LTC to home town admissible to unmarried Board's employees :

The unmarried Board's employees who have left their wholly dependent parents, sisters and minor brothers at their home town may also be given the benefit of LTC to visit hometown every year. This concession will be in lieu of all other LTC facilities admissible to Board's employee, parents, sisters and minor brothers.

- (l) Condition of 'residing with waived' in respect of spouse and children :

In cases where the Board's employee has left his/her spouse and the dependent children at a place other than his/her headquarters, he may be allowed LTC in respect of them from the place of their residence to home town in a block of two years or any place in India in a block of four years, as the case may be, but the reimbursement should in no case exceed the actual distance travelled by the family or the distance between Bombay and the place visited/home town, whichever is less.

7. Home Town.—'Home town' means the permanent home town or village as entered in the service book or other appropriate official record of the employee concerned or such other place as has been declared, by him, duly supported by reasons (such as, ownership of immovable property, permanent residence of near relatives, e.g. parents, brothers etc), as the place where he would normally reside but for his absence from such a station for service under the Board. The criteria mentioned below may be applied to determine whether the employee's declaration of home town may be accepted.

- (i) whether the place declared by the employee is the one which requires his physical presence at intervals for discharging various domestic and social obligations, and, if so, whether after his entry into service, the employee, had been visiting that place frequently.
- (ii) whether the employee owns residential property in that place or whether he is a member of a joint family having such property there ;
- (iii) whether his near relatives are resident in that place;
- (iv) whether, prior to his entry into the Board's service, the employee had been living there for some years. The criteria one after the other, need be applied only in cases where the immediately preceding criterion is not satisfied. Where the employee or the family of which he is a member owns residential or landed property in more than one place, it shall be left to the employee to make a choice of any such place as his home town giving reasons for the same, provided that the decision of the Head of the Department in which the employee is employed whether or not to accept such a place as the home town of the employee shall be final. Where the presence of near relations at a particular place is to be the determining criterion for the acceptance of declaration of 'home town', the presence of near relations should be of more or less permanent nature.

8. 1. Declaration of Home Town :

- (i) Every employee shall make a declaration of his home town. A declaration already made by an employee under the regulations in force before the commencement of these regulations shall be treated as the declaration made by him for the purpose of these regulations. Every new entrant to the Board's service shall make a declaration as to his home town before the expiry of six months from the date of his entry into the Board's service.
- (ii) The declaration made by an employee, other than a Head of a Department shall be subject in each case, to the acceptance by the Head of his Department who

shall satisfy himself about the correctness thereof after calling for such evidence as he may consider necessary. The effective date of declaration of home town shall be the date on which the employee made it and not the date of its acceptance by the Head of his Department or the date of communication conveying such acceptance. The declaration made by a Head of a Department shall be subject to the acceptance by the Deputy Chairman or the Chairman. A declaration made by an employee and accepted by his Head of Department, or the Chairman, as the case may be, under the regulations in force before the commencement of these regulations shall be treated as the declaration accepted by the Head of a Department, Dy. Chairman or Chairman for the purpose of these regulations.

- (iii) A declaration of 'home town' once made shall ordinarily be treated as final, but in exceptional circumstances the Head of a Department (and in the case of a Head of Department, the Chairman or the Deputy Chairman) may authorise a change in such declaration provided that such a change shall not be made more than once during the period of service of the employee. In the case of persons on deputation to the Board, such requests shall be granted only with the approval of the lending authority.
- (iv) The declaration of home town made after the prescribed time limit may be accepted by the Head of a Department (and in the case of a Head of a Department, by the Chairman or the Deputy Chairman) against the one chance for changing the declaration and this will be treated as a final declaration of home town and no further change of home town will be allowed in such cases.
- (v) The Head of a Department may, for his own convenience, maintain a register of home town in respect of employees in his Department.

2. Declaration of Home Town—Outside India

A Board's employee who declares subject to the satisfaction of the concerned authority, that his home town is outside India, will also be entitled to the LTC for visiting his home town, Board's assistance in such a case will be limited to the share of the fares for journeys—

- (i) upto and from the railway station (by the shortest route) nearest to the home town or
- (ii) the railway station for the nearest port of embarkation/d'sembarkation in India. The term 'nearest port' for this purpose means the port in India nearest to the home town of the Board's employee.

3. When the husband and wife are both Board's employees

The husband and wife who are both Board's employees could, at their option, choose to declare separate home town and both of them may claim the concession separately under the normal provisions of LTC Rules in respect of members of their respective families. This is, however, subject to the condition that if husband or wife avails the facility as the member of the family of the other, he or she will not be entitled for claiming the concession for self independently. The children shall be eligible for the benefit of one particular bloc as members of the family of one of parents only. All the other conditions for admissibility of LTC shall continue to be applicable as per normal provisions of the scheme.

9. Class of Accommodation :

(A) Journey between places connected by rail

- (i) When travelling by railways, employees will be entitled to Class of accommodation as follows :

Class I and II Officers : 2nd Class Air Conditioned two tier sleeper/1st Class.

Employee in receipt of : 2nd Class Air Conditioned of pay of Rs. 1665 two tier sleeper/1st Class a above.

Employees in receipt of : 2nd Class pay less than Rs. 1665

- (ii) The class of railway accommodation to which an employee and his family shall be entitled is the class to which he is entitled at the time the journeys are undertaken. It is permissible for an employee or his family or both to travel in a class higher or lower than that to which he or his family is entitled. The Board's liability shall be the fare by the entitled class or the actual expenditure whichever is less.

In case of air travel, an employee entitled to travel by 2nd Class Air Conditioned two tier sleeper/1st class will be reimbursed fare of 2nd Class Air Conditioned two tier sleeper.

- (iii) (a) An employee or his family members may avail themselves any concessional return journey tickets offered by the Railway authorities (e.g., seasonal concession, students concession, etc.) In conjunction with the LTC. It will be permissible while utilising such a concessional ticket to travel in any class higher or lower, than the entitled class.
- (b) Where an employee and/or his family avails of the concessional circular tour ticket offered by the Railway authorities in conjunction with the LTC, the fare at the normal rate for the entitled/actual expenditure between Bombay and home town by the shortest route shall be reimbursed to the employee. In the case of journeys on the basis of concessional circular four ticket for visit to any place in India, once in a bloc of four years, the reimbursement shall be the fare at the normal rate for the entitled class or actual expenditure between Bombay and the place visited by the shortest route.
- (iv) An employee who is normally entitled to travel by 1st Class may travel by 2nd Class in the deluxe air conditioned trains while availing himself of the concession.
- (v) When an employee or any member of his family perform the journey by a long route (which is not the cheapest) in two different classes of Railway accommodation, e.g., partly by 1st class to which he is entitled and partly by 2nd class, the reimbursement shall be the entitled class fare for the entire distance/actual expenditure whichever is less.
- (vi) Where an employee or his family or both travel by air or by road or by steamer between two places connected by rail, the expenditure on the Board's assistance shall be limited to what would have been admissible had the employee or his family travelled by rail in the authorised class or the actual expenses, whichever is less.

(vii) Entitlement for journey on LTC by Rajdhani/Shatabdi Express

Pay Range	Entitlement of Class
(a) Class I and II Officers	2nd Class A.C. two tier sleeper
(b) Class III employees drawing Rs. 2405 and above :	2nd Class A.C. two tier sleeper
(c) Class III employees drawing Rs. 1665 and above: but less than Rs. 2405	A.C. chair car
(d) Below Rs. 1665	

Re-imbursement shall be restricted to the 2nd class Fare by any other train for the distance travelled.

(B) Journeys between places not connected by rail :

(i) By road :

Where a Public transport system with vehicles running between fixed points, at regular intervals and charging fixed fare rates exists, the assistance will be the fare actually charged by such a system for the appropriate class of accommodation of the transport system.

The appropriate class means

- (a) Class I & II Officers :
- (b) Employees in receipt of pay of Rs. 1665 and above :
- (c) Employees in receipt of pay less than Rs. 1665

Any type of bus.

Any type of bus.

By ordinary bus only. May travel by express but in case of non-availability of seat in ordinary bus.

Fares are payable at half the rates for children between the ages of 3 and 12 years.

(ii) By air :

Board's employee may travel by air between places not connected by rail where an alternative means of travel is either not available or is more expensive.

(C) Journeys to Port Blair :

The journey upto the port of embarkation will be regulated as usual. From the port of embarkation to Port Blair, the entitlement is as below :

Basic Pay	M.V. Akbar	M.V. Majid	Others
(a) All class I & II Officers	Deluxe Class with attached toilet	I Class	Deluxe Cabin
(b) Class III employees drawing Rs. 2405 and above	Deluxe Class with attached toilet	I Class	I Class Cabin
(c) Class III employees drawing Rs. 1665 above but less than Rs. 2405	I Class with common toilet	I Class	I Class Cabin
(d) Class III employees drawing Rs. 1405 but less than Rs. 1665	A.C. Dormitory Class	II Class	II Class 'A' Cabin
(e) Class III employees drawing less than Rs. 1405	A.C. Dormitory Class	Sofa	II Class 'B' Cabin
(f) All Class IV employees	Bunk Class	Floor sitting	Bunk Class

(D) Entitlement for journey by sea on steamer

Basic Pay

- (a) Class I and II officers
- (b) Class III employees drawing Rs. 2405 and above
- (c) Class III employees drawing Rs. 1665 and above but less than Rs. 2405
- (d) Class III employees drawing Rs. 1405 and above but less than Rs. 1665
- (e) Class III employees drawing less than Rs. 1405
- (f) All Class IV employees

Class entitled

- Highest Class
- Highest Class
- If there be two classes, the lower class. If there be more than two classes, the middle or the second Class.
- If there be two classes, only the lower class. If there be three classes the middle or the second class.
- If there be four classes, the third class
- The lowest class

(E) Journeys by vehicles of the following categories are not recognised for purpose of LTC :

- (a) Private chartered vehicles including vehicles taken on hire by private parties from Tourism Development Corporation in public sector or State Transport corporation or transport undertakings of local bodies and run on charter by such private parties.
- (b) Vehicles whether owned, borrowed or hired by BPT employees.—However, travel by private buses operating as regular transport service from point to point at regular intervals on fixed fare rates,

with the approval of Regional Transport Authority/State Government does not amount to travel by private chartered bus. Journeys by the chartered bus shall be admissible for LTC only in those cases where the tour is wholly operated and conducted by ITDC/State Tourism Development Corporation either by their own buses or ITDC/State Tourism Development Corporation certify that the tour was actually conducted/operated by them and not by a private person/party.

- (c) Journey by a chartered rail coach is, also, not admissible unless the chartered tour is wholly operated

ed and conducted by a Central or State Undertaking.

(F) The temporary dislocation of surface transport cannot be taken as "non-availability of alternative means". The reimbursement in such cases will be restricted to entitled class of road/rail journey.

(G) When husband and wife are both Board's employees, the concession will be admissible to the family on the scale admissible to the husband or the wife and not both.

(H) (a) Special supplementary charges levied by the Railway from those travelling by Super Fast Express trains in reserved accommodation, is also reimbursable under the LTC in the same way as the amount of rail fares.

(b) The extra cost incurred for the reservation charges will be borne by the Board.

(c) Reimbursement of telegram charges paid to Railway authorities for reservation of berth on train in case of journeys on LTC is not admissible.

(d) No incidental expenses shall be admissible for journeys performed under the concession.

(I) Concession based on shortest route,—

(a) The Board's liability for the cost of railway fare between Bombay and the place visited by the employee or his home town, as the case may be, shall be limited to the share of the fare by the shortest route calculated on the 'through' ticket basis. The employee or his family members may travel by any route or halt anywhere on the way to or from the place visited by the employee, or home town, as the case may be, but the Board's assistance shall be limited to their share of the fare as above. Where the shortest route is disrupted due to accidents or other causes, the power to grant reimbursement by the actual route travelled may be exercised by the Head of Department.

(b) In cases where more than one mode or conveyance are available, e.g. where two places are connected by a direct bus as well as by a bus which plies by a longer route and where other public conveyances are also available and a doubt or difficulty is experienced in determining the shortest practicable routes the distance as ascertained from the local authorities concerned may be accepted for the purpose of local journeys.

Explanation :

The term 'Shortest route' shall carry the same interpretation as recognised for travel on duty.

(J) Journeys of weighted mileage for visiting home town.— If, for the entire leave travel journey or a part thereof, an employee has to pay railway fare on the basis of an assumed or weighted mileage (example, on Kalka-Simla Section) or at inflated rates (example, on Siliguri-Darjeeling Section) and if the fare for the total distance travelled by rail (including the fare on the basis of assumed or weighted mileage or at the inflated rate, as the case may be) be more than the fare for the initial distance at ordinary rates, the employee concerned shall be entitled to the travel concession irrespective of the actual distance between Bombay and the place visited, by the employee or his home town as the case may be. In such a case, the amount reimbursable by the Board to the employee shall be the difference between the cost of the actual railway fare (inclusive of the passenger tax) from Bombay to the place of visit or home town and the cost of railway fare (inclusive of the passenger tax) at ordinary rates from Bombay for both the outward and return journeys.

Note :

Pay limits prescribed in this regulation shall be revised to corresponding pay limit with respect to the revised scales whenever pay scales are revised.

10. Concession restricted within India :

(a) Any place in India will cover any place within the territory of India whether it is on the mainland, India or overseas connected by rail or partly connected by rail and partly connected by road or steamer services and not connected by rail. Any place in India includes the home town of the Board's employee also.

(b) When the concession to visit any place in India is proposed to be availed of by the employee of the Board and/or member(s) of his family, the intended place of visit should be declared by the Board's employee in advance to his Head of Department.

(c) The Board's employee and/or member(s) of his family, as the case may be, must visit the declared place to become eligible for making the LTC claim. The journey may be performed by any route to the declared place of visit but the claim will be regulated with reference to the shortest direct route on a through ticket basis between the headquarters and declared place of visit.

(d) The declared place of visit can be changed before the commencement of the journey, with the approval of the HOD and in case of HOD Chairman/Dy. Chairman, as the case may be. It cannot be changed after the commencement of the journey.

Exceptions —:

(a) If, however, it is established that the request for change cannot be made before the commencement of the journey owing to conditions beyond the control of the Board's employee, this condition may be relaxed by the HOD/Chairman/Dy. Chairman, as the case may be and the claim allowed.

(b) If the Board's employee while proceeding under 4 years LTC to a declared destination had to stop at a particular Station en route and hence could not visit the declared station due to circumstances beyond his control, his claim may be admitted provided that such intermediary station is en route to his declared destination.

11. Nature of Leave :

(i) The concession shall be admissible for journeys performed by the employee during regular/causal/special casual leave, maternity leave, irrespective of its duration. The concession shall not be admissible to an employee who proceeds on regular leave, or casual leave, special/maternity leave, as the case may be, and then resigns his post without returning to duty. The above cited condition shall not apply to journeys performed by the members of family of the employee.

(ii) The LTC cannot be availed during Sunday, optional Holidays or any other period of Holidays alone, which includes second and fourth Saturdays in case of Indoor staff.

(iii) The concession shall be admissible to an employee and his family in respect of only the outward journey from Bombay during leave preparatory to retirement, refused leave or terminal leave, provided that the concession had not been availed of earlier during that particular block of financial years. In such cases, the journey by both the employee and his family members shall commence within the period of leave.

(iv) An employee or his members or both shall be entitled to the concession irrespective of the actual period of his stay in his home town.

12 (1) Mode of preferring claims.—Cash reimbursement in respect of journeys to home town and in respect of journeys to any place in India once in a block of four years shall be made on presentation of claims in Travelling Allowance Bill forms with the usual certificate to the effect that

they had actually performed such journeys and travelled by the class of accommodation not lower than the one for which reimbursement is claimed.

(2) Prescribed Certificates.—Two Certificates, one from the concerned Head of Department and the other from the employee, as nearly as possible, as at Appendices I and II, shall be submitted to the Accounts Officer along with Travelling Allowance bill for travel concession.

(3) Obligatory evidence.—The employee shall inform the Head of his Department or an officer designated by the Head of Department in this behalf, before journeys for which assistance under these regulations is claimed are undertaken. He shall also produce such evidence of his having actually performed the journey, for example, serial numbers of railway tickets cash receipts, as the Accounts Officer may prescribe from time to time. Relaxation of a minor nature, viz., in respect of production of serial numbers of railway tickets or cash receipts for railway tickets, prior intimation to the Head of Department before the journeys are undertaken by the employee or their families or both under these regulations, may be made by the Head of Department, and in case of Head of Department by Deputy Chairman or Chairman, if he is otherwise satisfied in regard to the genuineness of the claim and the bonafides of the journey having been performed.

13. Record of assistance.—A record of all assistance granted under these regulations shall be suitably maintained. The record should be in the form of entries in the service sheet or other appropriate record and should indicate the date or dates on which the journey or journeys commenced. The authority responsible for the maintenance of the service sheet shall ensure that whenever an employee proceeds on leave and avails of the concession the fact that he has done so is indicated in the record.

14. Advance.—To enable an employee to avail of the travel concession, an advance may be granted on the following terms and conditions, namely :—

- (a) the amount of advance in each case shall be limited to 90 per cent of the estimated amount which the Board would have to reimburse in respect of the cost of journeys both ways;
- (b) Where the employee and the members of his family avail themselves of the travel concession separately, i.e. at different times, the advance may be drawn separately to the extent admissible and adjustment of claims may be made separately. Where, however, a consolidated advance is drawn by the employee in respect of the members of his family, the adjustment claims shall be drawn in a single bill;
- (c) the advance may be drawn for both the outward and return journeys of the employee or the members of his family or both at the time of commencement of the outward journey, provided that the period of leave taken by the employee or the period of anticipated absence of the members of their family does not exceed 90 days. Where the period of leave or the period of anticipated absence exceeds the said limit, the advance may be drawn for the outward journey only. Where an advance has been drawn for both the outward and return journeys and later it becomes clear that the period of absence of either the employee or the employee's family from Bombay is likely to exceed the said limit, one-half of the advance (in lump-sum) should be refunded to the board forthwith;

- (d) the advance in respect of the temporary employees and their families will be sanctioned subject to the production by them of surety of a permanent employee. The above will not be applicable to employees who have put in more than 5 years continuous service;
- (e) the advance will have to be refunded in full forthwith if the outward journey is not commenced within 60 days of the grant of the advance. In all cases the employee should produce railway or bus tickets etc. within ten days of drawal of advance;
- (f) the Travelling Allowance claim in adjustment of the advance drawn should be prepared within one month of the completion of the return journey; and within 3 months if no advance has been drawn;
- (g) the account of advance drawn for leave travel journeys will be rendered after completion of the journeys in the same way as for and advance of Travelling Allowance on tour;
- (h) the adjustment of the advance will be watched through appropriate registers maintained by the Accounts Officer;
- (i) Where an advance has been drawn by the Board's claim for reimbursement of the expenditure incurred on the journey shall be submitted within one month of the completion of return journey. On the Board's employees failure to do so, he shall be required to refund the entire amount of advance forthwith in one lump sum. No request for recovery of advance in instalments shall be entertained;
- (j) If the conditions laid down for grant of advance are not complied with or if the rules for granting advances for LTC have been violated, the Head of Department should charge penal interest i.e. 2-1/2 per cent above the rate of interest for purchase of conveyance (other than motor cars);
- (k) In case of an employee on deputation who avails of LTC immediately on reversion but before joining his parent office, the borrowing department may grant the advance in consultation with the lending department and endorse a copy to the lending department to enable them to watch the adjustment of the advance.

15. Head of account.—The expenditure on the concession shall be debited to the respective cost centres under the type, 530, "Leave Travel Concession".

16. Interpretation.—In all cases of doubt regarding the applicability of these regulations to any employee or their interpretation, the decision of the Chairman shall be final.

Provided that an employee aggrieved by any decision of the Chairman may within sixty days of the receipt of order, prefer an appeal to the Board and the Board may take such decision as deem fit.

17. Repeal and saving.—All regulations corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.